जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 115 प्रभात बीकानेर, मंगलवार, 18 नवम्बर, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

नीतीश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से किया इनकार, आखिर क्यों?

विशेषज्ञों की मानें तो, या तो वे एनडीए में अपनी अथॉरिटी साबित कर रहे हैं या फिर कोई और बड़ा खेल करना चाहते हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। बिहार विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत मिलने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और इस दौरान इस्तीफ़ा देने से इनकार करके बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी। इस कदम ने उनके अगले क़दमों को लेकर अटकलों को और बढ़ा दिया है और इससे नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के अंदर नई दरारें उजागर हो गई हैं।

- एनडीए की इकतरफा जीत के बाद भी नीतीश चुप हैं और उनकी चुप्पी से राजनैतिक हलकों में खलबली मच गई है, खासकर एनडीए में।
- नीतीश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। मौन और इनकार से नीतीश ने भाजपा से सौदेबाजी करने की ताकत बढ़ा ली है और जिस प्रकार भाजपा ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया है, उससे जाहिर है कि नीतीश अपनी नीति में सफल हो रहे हैं।
- लेकिन, नीतीश इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे, इस बार वे अपनी शर्तों पर सरकार बनाएंगे। समझा जाता है कि नीतीश ने स्पीकर और उपमुख्यमंत्री के पद पर दावा तो किया ही है, साथ ही बिहार के लिए विशेष पैकेज भी मांगा है।
- इसी बीच यह भी चर्चा है कि महागठबंधन ने नीतीश को समर्थन देने की पेशकश की है। नीतीश के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पाला बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

एनडीए की भारी जीत के बावजूद, नीतीश की चुप्पी और उनकी रणनीतिक मुद्रा ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे किसी प्लान बी की संभावना तलाश रहे हैं, जिसमें भाजपा शामिल न हो। शनिवार को भाजपा नेताओं ने दावा किया कि पार्टी हाईकमान को नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने पर “कोई आपत्ति नहीं” है, लेकिन जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर की गतिविधियां बताती हैं कि अंदर ही अंदर कोई जटिल सौदेबाजी चल रही है।

जेडीयू नेतृत्व से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने भाजपा को साफ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य सरकार ने एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ अपील की

जयपुर, 17 नवंबर। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ करीब ढाई माह बाद अब राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। परीक्षा केन्द्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था। इसके अलावा आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर भी उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था। यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही

- हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पेपर लीक के कारण एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को 28 अगस्त को रद्द किया था।

और गलत की छंटनी कर सकती हैं तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 8 सितम्बर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। वहीं एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावी हार के लिए बलि का बकरा ढूंढ रही है कांग्रेस

न कोई जिम्मेदारी, न जवाबदेही, फिर सफलता कैसे मिलेगी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। राहुल गांधी और उनके साथियों ने बिहार में मिली करारी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, साथ ही, सूत्रों से पता चला है कि पार्टी नेतृत्व ने पंजाब पीसीसी अध्यक्ष राजा वड़िंग से इस्तीफ़ा देने को कह दिया है।

- कांग्रेस ने बिहार में हार को अस्वीकार कर दिया है और “वोट चोरी” को ही हार का कारण बताया जा रहा है।
- वहीं पंजाब में जीत का दावा कर रही कांग्रेस उपचुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाई तो पीसीसी अध्यक्ष राजा वडिंग से इस्तीफा लेने की तैयारी की जा रही है, जबकि पंजाब में भूपेश बघेल बतौर प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल के कहे अनुसार काम कर रहे थे।
- मंगलवार को राहुल गांधी ने उन 12 राज्यों के पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं की बैठक बुलाई है, जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरु हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि यह सब बिहार की हार से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी पार्टी की दुर्दशा का एक बड़ा कारण राहुल के प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी चला रहे के.सी. वेणुगोपाल की मनमानी को माना जा रहा है।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब पंजाब उपचुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही है और अपनी ज़मानत भी नहीं बचा सकी।

कांग्रेस के लिए यह एक नई गिरावट है, जबकि वह लगातार दावा करती रही है कि चुनाव होते ही वह राज्य की सत्ता में लौट आएगी।

लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।

पंजाब कांग्रेस को के.सी. वेणुगोपाल, एआईसीसी प्रभारी भूपेश बघेल के ज़रिए चला रहे हैं। बघेल, वेणुगोपाल को रिपोर्ट करते हैं और वहां एक समूह भी सक्रिय है, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष भी शामिल थे, पर जिन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।

राहुल के राज में पार्टी में न कोई ज़िम्मेदारी रही है, न जवाबदेही, और अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि राहुल और उनका समूह केवल “वोट चोरी” की बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं, और वे यह मानने को तैयार ही नहीं है कि बिहार में उन्हें करारी हार मिली है।

उच्च स्तर के सूत्रों के अनुसार, नाराज़ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि पार्टी हर जगह क्यों हार रही है, फैसले कौन ले रहा है और किसी पर भी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही।

स्पष्ट है कि खड़गे का निशाना वेणुगोपाल, और पार्टी को राहुल के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश की निर्वासित प्र.मंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड

बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित इंटरनैशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के विरूद्ध अपराधी करार देकर मौत की सजा सुनाई

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 नवम्बर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक ट्रिब्यूनल ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के दौरान अपराध करने और पुलिस को घातक कार्रवाई के आदेश देने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई है।

- शेख हसीना ने फैसले को एकतरफा और पक्षपातपूर्ण करार दिया और कहा कि कथित इंटरनैशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल में किसी भी अन्य देश का कोई भी कानूनी विशेषज्ञ नहीं था।
- बांग्लादेश की तरफ से भारत सरकार से लिखित में मांग की गई है कि शेख हसीना फरार अपराधी हैं, उन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, ऐसा नहीं करना गैर मित्रतापूर्ण कृत्य माना जाएगा।
- शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह वही पार्टी है, जिसने पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी।

प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाए जाने के साथ ही, उनकी देश वापसी की मांग तेज़ हो गई है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने भारत से मांग की है कि वह शेख हसीना को वापस भेजे, जो आंदोलन के बाद भारत आ गई थीं।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पहले ही हसीना को उनके अपराधों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए वापस भेजने की मांग कर चुकी है। लेकिन भारत ने अब तक इस मांग को न तो माना है और न ही अंतरिम सरकार के दावे को मान्यता दी है। शेख हसीना ने अपनी तरफ से कहा है कि अंतरिम सरकार ने इन्टरनैशनल क्राइम ट्रिब्यूनल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘स्पीकर तय करें, न्यू ईयर कहां मनाना चाहते हैं’

नई दिल्ली, 17 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने

- सीजेआई ने तेलंगाना स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के दस विधायकों की अयोग्यता पर जल्दी फैसला करें अन्यथा इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।

नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष ने बीआरएस के 10 विधायकों जो कांग्रेस में शामिल हो गए, के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अदालत द्वारा तय समयसीमा में निर्णय नहीं लिया। चीफ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप का दबाव काम आया, भारत अमेरिका से एलपीजी खरीदेगा

भारत ने अमेरिका से एक साल की डील की है, जिसमें 22 लाख टन एलपीजी खरीदी जाएगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 नवंबर। मोदी सरकार का अमेरिकी दबाव के आगे झुकने का पहला ठोस सबूत सामने आया है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों ने अमेरिकी लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) आयात के लिए एक साल का समझौता किया है। यह भारतीय बाज़ार के लिए अमेरिकी एल.पी.जी. का पहला व्यवस्थित अनुबंध है।

- सरकार द्वारा इसे देश के ऊर्जा स्रोतों को विविधता देने का प्रयास बताया जा रहा है, पर आलोचक इसे ट्रंप की धमकी के आगे घुटने टेकना बता रहे हैं।
- जानकार सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख तेल कंपनियाँ अमेरिका से एलपीजी खरीदेंगी।
- भारत की एलपीजी की आवश्यकता अधिकांशतः सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और कुवैत से पूरी होती है। इस डील से इन देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी।

हालाँकि इस कदम को देश के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और व्यापार समझौते की बातचीत के बीच अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, लेकिन साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की धमकाने वाली दबाव नीति के आगे झुक गई है।

पैट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम, कुख्यात एप्सटीन फाइलों में आने के कारण सवालों के घेरे में है, ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इस सौदे को “ऐतिहासिक पहल” बताया।

उन्होंने कहा, “दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से बढ़ रहे एल.पी.जी. बाज़ारों में से एक, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खुल गया है। भारत के लोगों को सुरक्षित और सस्ती एल.पी.जी. उपलब्ध कराने के प्रयास में हम लगातार अपने स्रोतों में विविधता ला रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारतीय पी.एस.यू. तेल कंपनियों ने 2026 के लिए लगभग 2.2 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) एल.पी.जी., जो हमारे सालाना आयात का लगभग 10 प्रतिशत है, यह समझौता वर्ष 2026 के लिए अमेरिका के खाड़ी तट से आयात करने के लिए है। यह भारतीय बाज़ार के लिए अमेरिकी एल.पी.जी. का पहला औपचारिक अनुबंध है।”

जानकार सूत्रों के अनुसार, तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों– इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बी.पी.सी.एल.) और हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन (एच.पी.सी.एल.) ने अगले साल के लिए अमेरिकी एल.पी.जी. आयात का संयुक्त टेंडर शेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जी ट्रेडिंग को दिया है। सौदे का व्यावसायिक विवरण उपलब्ध नहीं है।

भारत में एल.पी.जी. का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाना पकाने के ईंधन के रूप में होता है और इसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर और कुवैत जैसे देशों से आयात होता है। एक अधिकारी ने इस परिवर्तन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट के आतंकी उमर का साथी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 17 नवंबर। एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट को अंजाम देने में सह साजिशकर्ता की भूमिका निभाने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जसीर बिलाल वानी बताया जा रहा है। इसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने

- एनआईए द्वारा श्रीनगर से गिरफ्तार जसीर बिलाल वानी ने विस्फोट को अंजाम देने में सक्रिय रुप से काम किया था।

बताया कि वानी ने विस्फोट को अंजाम देने के लिए आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी के साथ सक्रिय रूप से काम किया था।

आतंकवाद रोधी एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अनंतनाग के काजीगुंड निवासी वानी ने कथित तौर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सऊदी अरब में मदीना के नज़दीक भीषण सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत

मृतकों में अधिकांश हैदराबाद के थे और उमराह के लिए सऊदी अरब गए थे

रियाद, 17 नवंबर। सऊदी अरब में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई है। मरने वालों में अधिकतर हैदराबाद के निवासी थे। यह हादसा उस समय हुआ, जब उमराह के लिए गए लोगों को लेकर जा रही बस एक तेल टैंकर से टकरा गई। सऊदी अरब के मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, हादसा मदीना के नजदीक हुआ और हादसे में मरने वाले भारतीय उमराह यात्री हैं। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है।

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार, उमराह गए लोगों को लेकर मक्का से मदीना जा रही बस रास्ते में डीजल टैंकर से टकरा गई। हादसा स्थानीय समय के अनुसार, सुबह करीब 1.30 बजे मुहरास या मुफरिआत इलाके में हुआ, जो मदीना के करीब है। हादसे के समय कई यात्री सो रहे थे। टक्कर लगते ही बस आग की लपटों में घिर गई और लोगों को बचने का भी समय नहीं मिला। हादसा इतना भयानक था कि मृतकों की पहचान करना भी मुश्किल है। हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने बताया है कि सऊदी अरब में हुए बस हादसे में 45 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों में अधिकतर हैदराबाद के निवासी हैं। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बताया कि बीती 9 नवंबर को हैदराबाद से 54 लोग उमराह के लिए जेद्दाह गए थे और इन लोगों को 23 नवंबर को

- गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह 1:30 बजे हुआ था, हादसे के समय सभी यात्री सो रहे थे और टक्कर लगते ही बस में आग लग गई।
- हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने बताया कि हादसे के समय बस में 46 लोग सवार थे, सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है, जिसका इलाज चल रहा है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
- हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री जयशंकर से मृतकों को भारत लाने की अपील की है।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिजनों को पाँच-पाँच लाख रूपए की सहायता देने की घोषणा की।

वापस आना था। इन 54 में से चार लोग एक कार से मक्का से मदीना जा रहे थे और चार अन्य लोग मक्का में ही रुक गए थे। बाकी लोग हादसे का शिकार हुई बस में सफर कर रहे थे। हादसे के समय बस में 46 लोग सवार थे। हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि हमें जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक 45 लोग मारे गए हैं और ये लोग 23 नवंबर को हैदराबाद लौटने वाले थे। एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने भी बताया कि हमें जो शुरुआती रिपोर्ट मिल रही है, उसके तहत हादसे में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हम पीड़ित परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से हादसे में मारे गए लोगों के शवों को वापस भारत लाने में मदद की अपील की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सऊदी अरब हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दाह का महावाणिज्य दूतावास हरसंभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे अधिकारी भी सऊदी अरब सरकार के अधिकारियों के संपर्क में हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वी. श्रीनिवास ने मुख्य सचिव का पद संभाला

जयपुर, 17 नवंबर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास ने सोमवार को राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें औपचारिक रूप से चार्ज सौंपा। चार्ज लेने से पहले दोनों अफसरों ने सचिवालय भवन के प्रवेश द्वार स्थित गणेश मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की।

चार्ज संभालने के बाद श्रीनिवास ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि सुधांश पंत को सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की ओर से विदाई दी गई। पंत अब दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में विशेष अधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।